भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(माओवादी)

केंद्रीय कमेटी

प्रेस विज्ञप्ति

27 जनवरी, 2022

31 जनवरी को विश्वासघात दिवस मनाने के संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान को सफल बनावें!
भाजपा सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में तहसील, मंडल/जनपद एवं जिला केंद्रों में जुझारू प्रदर्शन आयोजित करें!

भाजपा की केंद्रीय सरकार द्वारा तीन कृषि कानूनों वापस लेते समय जो वादे किए गए थे, उन्हें पूरा न करने के विरोध में 31 जनवरी को विश्वासघात दिवस मनाने के संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान को सफल बनाने भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की केंद्रीय कमेटी देश के समूचे किसानों का आह्वान करती है. मजदूर कानूनों में पूंजीपतिपरस्त संशोधनों के खिलाफ देशव्यापी मजदूर संगठनों के आह्वान पर 23, 24 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाने देश के समस्त संगठित व असंगठित मजदूरों, उत्पीड़ित वर्गों व उत्पीड़ित सामाजिक तबकों का आह्वान करती है.

किसानों के सामने सिर झुकाकर कृषि कानूनों को वापस लेते हुए केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनाने, किसान आंदोलन के कार्यकर्ताओं पर लगाए गए केसों को वापस लेने, आंदोलन के दौरान प्राण गंवाने वाले किसानों को मुआवजा देने के वादे किए. परंतु आज तक एमएसपी कानून बनाने के मामले में कमेटी गठित करने को लेकर सरकार ने कोई घोषणा नहीं की कि उसका स्वरूप और कामकाज कैसा रहेगा. आंदोलन के दौरान किसानों पर जबरन लगाए गए अवैध केसों को वापस लेने की कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गयी. हरियाणा में 48,000 किसानों पर 278 मामलों में पुलिस ने एफआईआर दाखिल किए. इनमें से 87 एफआईआर वापस लिए गए जबकि उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश राज्यों में इस सिलसिले को अपनाया ही नहीं गया. आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले करीबन एक हजार से भी ज्यादा किसानों को मुआवजा देने के वादे को भी सरकार ने नहीं निभाया.

केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के बेटे ने लखिमपूर–खीरी में आंदोलनकारी किसानों पर तीन गाड़ियां चढ़वाकर 6 किसानों की हत्या की. उसका विरोध करने वाले किसानों पर अपने अनुयायियों के साथ मिलकर मिश्र के बेटे ने गोलियां बरसायी जिसमें चार लोगों की जानें गयीं. सरकार ने यह झूठा आरोप लगाकर कि उनकी हत्या विरोध जताने वाले किसानों ने ही की, उन पर हत्या का इल्जाम लगाकर एफआईआर दाखिल किया. केंद्रीय मंत्री मिश्र को मंत्रिमंडल से हटाने के किसानों की मांग पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया.

किसानों के प्रति सरकार के इस अड़ियल रवैये के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने 31 जनवरी को देश भर में सभी तहसील/मंडल, जिला केंद्रों में प्रदर्शन आयोजित कर विश्वासघात दिवस मनाने का आह्वान दिया. फरवरी 23, 24 तारीखों में केंद्र सरकार की मजदूरविरोधी नीतियों के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल आयोजित करने केंद्रीय मजदूर संगठनों ने आह्वान किया. एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग को भी जोड़कर इस हड़ताल में शामिल होने संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों का आह्वान किया.

हमारी पार्टी इन मांगों का समर्थन कर रही है. इन आंदोलनों में भाग लेने देश की जनता का आह्वान करती है.

पांच राज्यों के चुनावों को नजर में रखकर भाजपा सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लिया है, यह

बात दिन–ब–दिन और स्पष्ट हो रही है. कृषि कानूनों को वापस लेने के कुछ ही दिन बाद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने यह कहा कि उनकी सरकार कृषि कानूनों को फिर से अमल करेगी. हालांकि सरकार के इस रवैये का जनता द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रकट हो रहा है, परंतु साम्राज्यवादियों की देखरेख में देश की जनता का दमन करने वाले देश के दलाल नौकरशाही पूंजीपति, सामंती वर्गों व उनका प्रतिनिधित्व करने वाली केंद्र, राज्य सरकारों के खिलाफ देशव्यापी मजबूत आंदोलन का निर्माण करने की जरूरत है.

इसके तहत संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के मुताबिक 31 जनवरी को देशभर में सभी तहसील, मंडल/जनपद, जिला पंचायत कार्यालयों के सामने जुझारू प्रदर्शन व रैलियां आयोजित करने, 23 व 24 फरवरी को आयोजित होने वाले मजदूर संगठनों के देशव्यापी हड़ताल में जुझारूपन के साथ शामिल होने हमारी केंद्रीय कमेटी देश के समस्त किसानों, मजदूरों का आह्वान करती है. साथ ही तमाम बुद्धिजीवियों, छात्रों, नवजवानों को इन आंदोलनों में शिरकत करने का भी आह्वान करती है.

अभय,

प्रवक्ता

केंद्रीय कमेटी,

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(माओवादी)